LOK SABHA

Monday, March 28, 1977/Chaitra 7 1899 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

MEMBERS SWORN

Shri Bindhyeshwari Prasad Mandal (Madhepura)

Shri Ebrahim Sulaiman Sait (Manjeri)

Shri Sreekantan Nair (Quilon)

Shri Narendrasingh Yadvendrasingh (Damoh)

Shri Hemvati Nandan Bahuguna (Lucknow)

Shri Ram Lal Rahi (Misrikh)

Shri Ram Nihor Rakesh (Chail)

Shri Saradish Roy (Bolpur)

Shri Gadadhar Saha (Birbhum)

Shri Ramubhai Rabjibhai Patel (Dadra and Nagar Haveli)

11.55 hrs.

ADDRESS BY THE VICE-PRESIDENT ACTING AS PRESIDENT

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table a copy of the Address by the Vice-President acting as President to both Houses of Parliament assembled together on the 28th March, 1977.

Address by the Vice-President acting as President

माननीय सदस्यगण,

मैं नई लोक सभा के सदस्यों को बधाई देता हूं और छटी संसद् के संयुक्त अधिवेशन में आप सब का स्वागत करता हूं।

इस अवसर पर जब हम एक सौम्य और परिचित चेहरा नहीं देखते तो मेरे विचार हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर जाते हैं, जो एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, विवेकपूर्ण सलाहकार, अनुभवी अगुवा तथा सज्जन पुरुष थे। आज हम उनके निधन पर शोक प्रकट करते हैं और बेगम आबिदा अहमद को अपनी हार्दिक संवेदनायें देते हैं।

अभी जो आम चुनाव हुआ है उससे प्रभावपूर्ण तथा निर्णायक ढंग से यह सिद्ध हो गया है कि जनता को अपनी ताकत, लोकतन्त्रात्मक प्रक्रिया की जीवन-शक्ति, जिसकी जड़ जमी है, पर कितना भरोसा है। जनता ने प्रशासक के मनमानेपन तथा व्यक्ति-पूजा के अभ्युदय तथा गैर संवैधानिक शक्ति केन्द्रों के विरुद्ध वैयक्तिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र तथा विधि-नियम के पक्ष में अपना स्पष्ट निर्णय दिया है। यह चुनाव हमारी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की एक स्वस्थ दो-दलीय प्रणाली के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील-पत्थर है।

मेरी सरकार जनता द्वारा दिए गए निर्णय को हर तरह से पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। ऐसा करने में यह मान कर नहीं चला जाएगा कि जनता कुछ नहीं जानती और

सरकार ही सभी उत्तर और हल जानती है। पिछले दो वर्षों में लोगों पर कई अत्याचार किए गए तथा उन्हें असीम कष्ट झेलने पड़े, और कई लोगों की तो जानें भी गईं। इस दुःखद अनुभव के कारण यह बात कहनी पड़ी।

माननीय सदस्यगण, नई सरकार ने तीन दिन पहले कार्यभार सम्भाला है। अभी जो ये कई उपाय करना चाहती है उनकी विस्तृत योजना बनाने का अभी समय नहीं मिला है। ये उपाय इस वर्ष यथासमय किए जाएंगे और आपके सामने पेश किए जाएंगे। पर, फिर भी, कई कामों पर तत्काल ध्यान देना है और सरकार इन्हें तुरन्त अपने हाथ में लेगी।

सबसे पहला काम है जनता की मौलिक स्वतंत्रताओं और नागरिक अधिकारों पर रोक हटाना, जिससे विधि-नियम तथा प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार फिर से स्थापित हो। 1971 में जिस बाह्य आपातकाल की घोषणा की गई थी उसे मेरे द्वारा कल रद्द कर दिया गया है। सरकार निम्नलिखित कदम उठाएगी :—

(i) पिछले दो सालों में आंतरिक सुरक्षा कानून का जो घोर दुरुपयोग हुआ, उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी, जिससे इसे रद्द किया जा सके और इस बात की जांच की जा सके कि न्यायालयों में जाने के अधिकार को बरकरार रखते हुए देश की सुरक्षा तथा आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए वर्तमान कानून को और सशक्त बनाने की आवश्यकता है या नहीं।

(ii) इस आशय का कानून बनाया जाएगा जिससे यह सुनिश्चय हो सके कि कोई भी राजनीतिक अथवा सामाजिक संगठन पर पाबंदी न लगाई जाए, जब तक पर्याप्त आधार न हो और इस संबंध में न्यायिक जांच न की जा चुकी हो।

(iii) आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर रोक संबंधी अधिनियम को रद्द किया जाएगा। विधायिकाओं की कार्यवाहियों को छापने के प्रेस का अधिकार फिर से लौटाया जाएगा।

(iv) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम संशोधन में भ्रष्ट आचरणों की जो व्याख्या की गई है तथा जिन कुछ व्यक्तियों के चुनाव अपराध को न्यायालयों की संवीक्षा से बाहर रखकर संरक्षण दिया गया है, उन्हें रद्द किया जाएगा।

इस वर्ष के दौरान, जनता तथा संसद्, संसद् तथा न्यायपालिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका, राज्य तथा केन्द्र, नागरिक तथा सरकार में संतुलन फिर से लाने के लिए, जिसकी व्यवस्था हमारे संविधान के निर्माताओं ने की थी, संविधान में संशोधन करने की एक व्यापक योजना आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। इसके अन्तर्गत अनुच्छेद 352 (तीन सौ बावन) के प्रावधानों का संशोधन शामिल है, जिनसे आपातकाल की घोषणा करने के अधिकार तथा सम्बद्ध अनुच्छेदों के दुरुपयोग पर रोक रखी जा सके, जिससे कि इस बात का सुनिश्चय हो सके कि राष्ट्रपति शासन संविधान में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुसार ही लागू हो, न कि किन्हीं बाहरी उद्देश्यों से।

पिछले कुछ समय से एक जो गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुई है वह यह है कि सूचना तथा जनसंपर्क माध्यमों की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता खत्म हो गई है। मेरी सरकार ऐसे उपाय करेगी जिनसे इन माध्यमों को लोकतंत्र में उचित स्थान दिया जा सके। ऐसे उपाय भी किए जायेंगे जिनसे यह सुनिश्चय हो सके कि आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म-प्रभाग तथा अन्य सरकारी माध्यम उचित तथा निष्पक्ष तरीके से काम करें।

पिछले साल इस देश के कई इलाकों में परिवार नियोजन का कार्यक्रम जिस प्रकार से

चलाया गया उससे जनता में जितना आक्रोश देखा गया वह पहले कभी नहीं देखा गया। इससे इस कार्यक्रम को, जो राष्ट्र के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, भारी नुकसान पहुंचा। परिवार नियोजन एक ऐच्छिक कार्यक्रम तथा एक व्यापक नीति के अभिन्न अंग के रूप में जोरदार ढंग से चलाया जाएगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृ-केन्द्र और बाल कल्याण, परिवार-कल्याण, महिला-अधिकार तथा पौष्टिक आहार शामिल हैं।

आर्थिक क्षेत्र में सरकार 10 वर्षों की अवधि में गरीबी हटाने के लिए वचनबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षाकृत उपेक्षा से अर्थ-व्यवस्था में एक भयानक असंतुलन उत्पन्न हुआ, जिससे लोग गांव से शहरों की ओर जाने लगे हैं। किसानों को अपने उत्पादन का उचित दाम नहीं मिला है। कृषि तथा सम्बद्ध विकासों के लिए विनियोजन बहुत ही अपर्याप्त है और गांवों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर बहुत कम ध्यान दिया गया। एक लाख से ज्यादा गांवों में पीने के पानी जैसी प्राथमिक सुविधा भी नहीं है। मेरी सरकार रोजगार उन्मुख नीति अपनाएगी, जिसमें कृषि विकास, कृषि उद्योग, छोटे और कुटीर उद्योगों को, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में प्राथमिकता मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकताओं के प्रावधानों तथा समग्र ग्रामीण विकास को भी ऊंची प्राथमिकता दी जाएगी। पंचवर्षीय योजना की यथासंभव समीक्षा की जाएगी योजना की प्रक्रिया में फिर से प्राण संचार किया जायेगा और छठी पंचवर्षीय योजना पर अविलंब काम शुरू होगा। इस साल बाद में अंतिम बजट पेश करते समय उन आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी जिन्हें चलाने का प्रस्ताव है।

अब मैं वैदेशिक संबंधों पर आता हूं। मेरी सरकार उन सभी वायदों को निभाएगी जो पिछली सरकार कर चुकी है। यह समानता और परस्पर सद्भाव के आधार पर सभी पड़ोसी तथा विश्व के अन्य देशों के साथ मैत्री भाव रखेगी और गुट निरपेक्षता की सही नीति अपनाएगी। मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि मेरी सरकार अगले महीने के प्रारम्भ में गुटनिरपेक्ष समन्वयात्मक ब्यूरो की बैठक की मेजबानी करेगी। मेरी सरकार सभी विकासशील राष्ट्रों के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग तथा संबंधों को भी मजबूत करने पर विशेष ध्यान देगी।

माननीय सदस्यगण, आपका वर्तमान अधिवेशन छोटा होगा, जिसमें वित्तीय मामलों—संघ की पूरक मांगों, राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत राज्यों, और आम बजट के संबंध में वोट आन एकाउन्ट, रेल बजट तथा राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों के बजट—पर तत्काल ध्यान देना होगा। आगामी महीनों में आपके सामने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है। आज राष्ट्र को आपसे बहुत बड़ी अपेक्षा है और मेरा विश्वास है कि आप उन कार्यों को, जो आपके सामने सरकार द्वारा पेश किए जाएंगे, लगन और तत्परता से पूरा करने में अपना सहयोग देंगे। मैं इन कार्यों की ओर आपका आह्वान करता हूं और आपकी सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।

Honourable Members,

I extend my felicitations to the members of the new Lok Sabha and welcome you all to the joint session of the Sixth Parliament.

On this occasion when we miss his benign and familiar presence my thoughts go to our late President Shri Fakhruddin Ali Ahmed in whom we have lost an elder statesman, a wise counsellor, an experienced leader, and a perfect gentleman. We mourn his loss today and convey our sincere and heartfelt condolences to Begum Abida Ahmed.

The General Election just concluded has effectively and decisively demonstrated the power of the people, the vitality of the democratic process in India and the deep root that it has taken. The people have given a clean verdict in favour of individual freedom, democracy and the rule of law and against executive arbitrariness, the emergence of a personality cult and extra-constitutional centres of power. The election marks an important milestone in the evolution of our democratic polity into a healthy two-party system.

My Government pledges itself to fulfil in every way the mandate given to it by the people. In doing so, it will not take the people for granted or assume that they know nothing and that the Government alone knows all answers and solutions. The traumatic experience of the last two years during which many atrocities were committed on the people and they had to undergo untold sufferings and some have even died, has brought home the relevance of this.

Honourable Members, the new Government has taken charge only three days ago. It has not had the time to work out the details of the various measures it intends to adopt. This will be done in due course during the year and placed before you. Nevertheless, there are some urgent tasks to be attended to and the Government will take them in hand immediately.

The most urgent task is to remove the remaining curbs on the fundamental freedoms and civil rights of the people, to restore the rule of law and the right of free expression to the Press. The external emergency proclaimed in 1971 has been revoked by me yesterday. The Government will also take the following measures:

(i) Having regard to the gross abuse to which the Maintenance of Internal Security Act has been put during the last two years, a thorough review of the Act will be undertaken with a view to repealing it and examining whehter the existing laws need further strengthening to deal with economic offences and security of the country without denying the right of approach to courts.

(ii) Legislation will be introduced to ensure that no political or social organisation is banned except on adequate grounds and after an independent judicial enquiry.

(iii) The Prevention of Publication of Objectionable Matters Act will be repealed. Immunity which the Press enjoyed in reporting the proceedings of legislatures will be restored.

(iv) The amendment to the Representation of Peoples Act which redefined corrupt practices and afforded protection to electoral offences by certain individuals by placing them beyond the scrutiny of the courts, will be repealed.

During the course of the year, a comprehensive measure will be placed before you to amend the Constitution to restore the balance between the people and Parliament, Parliament and the Judiciary, the Judiciary and the Executive, the States and the Centre, the citizen and the Government that the founding fathers of our Constitution had worked out. This will include provisions to amend Article 352 to prevent the abuse of the power to declare emergency and of the relevant Articles to ensure that President's Rule is imposed strictly in accordance with the objectives mentioned in the Constitution and not for extraneous purposes.

One of the very serious developments in the recent past was the erosion of the freedom and impartiality of the media of publicity and information. My Government will take steps to restore to the media their due place in a democracy. Steps will also be taken to ensure that All India Radio, Doordarshan, Films Division and other Government media function in a fair and objective manner.

Nothing has roused public anger and resentment so much as the manner in which the family planning programme was implemented last year in several parts of the country. This has caused a major set back to the programme which is vital for the welfare of the nation. Family planning will be pursued vigorously as a wholly voluntary programme and as an integral part of a comprehensive policy covering education, health, maternity and child-care, family welfare, women's rights and nutrition.

In the economic sphere, the Government is pledged to the removal of destitution within a definite time-frame of 10 years. Relative neglect of the rural sector has created a dangerous imbalance in the economy leading to migration of people from rural areas to urban centres. The farmer has been denied reasonable and fair price for his products. Allocations for agriculture and related developments have been grossly inadequate and the need to improve conditions in the villages has received scarce attention. More than a lakh of villages do not even have the most elementary facilities for drinking water. My Government will follow an employment-oriented strategy in which primacy will be given to the development of agriculture, agro-industries, small and cottage industries especially in rural areas. High priority will also be given to the provisions of minimum needs in rural areas and to integrated rural development. To the extent possible at this point of time, the Fifth Five Year Plan will be reviewed. The planning process will be revitalised, and work on the Sixth Five Year Plan will be taken up without delay. My Government will announce at the time of the presentation of the final budget later this year the details of the economic programme that is proposed to be followed.

I now come to external relations. My Government will honour all the commitments made by the previous Government. It stands for friendship with all our neighbours and other nations of the world on the basis of equality and reciprocity and will follow a path of genuine non-alignment. I am glad to say that my Government will be hosting a meeting of the Non-aligned Co-ordinating Bureau early next month. My Government will also give very special attention to the strengthening of ties and economic and technical co-operation with all developing nations.

Honourable Members, your present session will be a short one in which you will have to attend to urgent financial business—the Supplementary Demands of the Union and the States under President's Rule, and the Vote on Account regarding the General Budget, the Railway Budget and the budgets of States under President's Rule. A heavy and busy schedule lies ahead of you in the coming months. There is today a mood of expectancy in the country and I trust that you will co-operate fully in attending to the business that will be placed before you by Government, with thoroughness and expedition. I commend you to your tasks and wish you all sucess.

Jai Hind.